formulated schemes to introduce new Agricultural Education System in the country; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir. There is a need to reorient the syllabus at under graduate Level to meet the emerging needs of the changing agricultural scenario.

(b) A Deans' Committee has been constituted to look into the requirements of (a) above.

(c) Does not arise.

**Production of traditional varieties of Rice**

5638. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to ensure that traditional varieties of rice are grown in India;

(b) if so, the details of schemes to encourage farmers to continue cultivation of traditional rice varieties;

(c) whether any funds are available for this purpose; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) There is no proposal to ensure that only traditional varieties of rice are grown on commercial scale, other than to ensure the conservation of such genetic stock of traditional rice varieties on a systematic way so as to be useful for future breeding programmes.

(b) to (d) Question do not arise.

**Criteria for the Allotment of Houses to Fishermen**

5639. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the criteria for the allotment of houses to the families of fishermen under the Scheme of Model Fishermen Village; and

(b) the target under the scheme of 'fishermen village' for the year 1995-96, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) National Welfare of Fishermen Scheme has three components, one of which is 'Development of Model Fishermen's Village', under which there is provision for construction of houses for the fishermen. The allotment of houses to the fishermen under this component has been left to the concerned State Government. Under the scheme, the annual target is fixed in terms of number of villages to be developed in the Country and no State-wise targets are fixed. The target for 1995-96 is for development of 26 Model Fishermen's Villages.

**बागवानी के विकास हेतु भूमि का सर्वेक्षण**

5640. **श्री नरेश यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी समाप्त करने और उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए बागवानी योग्य कुल भू-क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम):** (क) से (ग) सारे देश के लिए अभी तक कोई सुव्यवस्थित सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया है। तथापि, कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में बागवानी के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी परीक्षण आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित राज्य में विभिन्न बागवानी वाली फसलों के क्षेत्र कवरेज में प्रक्षेपण शामिल है।

ये परीक्षण अभी तक 10 राज्यों में पूरे किये जा चुके हैं और अन्य 6-राज्यों में प्रगति पर हैं।

## कृषि की उन्नत प्रणालियां

5641. **श्री नरेश यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों को कृषि की उन्नत प्रणालियों की जानकारी देने के लिए क्या-क्या पद्धतियां अपनाई जा रही हैं और इस संबंध में वांछित सफलता न मिलने के क्या कारण हैं;

(ख) देश में विकसित देशों की तुलना में चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, दलहनों और तिलहनों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन कितना-कितना है;

(ग) क्या सरकार प्रयोगशालाओं में विकसित की गई प्रणालियों को कार्यरूप देने और किसानों को तदनुरूप प्रशिक्षण देने के कार्य में निजी और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार):** (क) किसानों को कृषि संबंधी उन्नत प्रणालियों की जानकारी देने संबंधी विधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) खेत पर ही मार्गदर्शन तथा सलाह; (2) प्रदर्शन; (3) प्रशिक्षण; (4) अध्ययन दौरे; (5) प्रिंट एवं जन संचार माध्यमों से सहायता; (6) प्रदर्शनियां/कृषि मेले; (7) फार्मर्स फील्ड स्कूल आदि। कृषकों को प्रौद्योगिकी के अन्तरण में उक्त विधियां सामान्यतः उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

(ख) विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) जी, हां।

(घ) अनुसंधान में निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहल तथा विस्तार में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता अब कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध है। गैर सरकारी संगठन पनधारा तथा कृषि विस्तार कार्यक्रमों में कार्यरत हैं। कृषकों के लिए दीर्घावधि व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है, 81 कृषि विज्ञान केन्द्र स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन राज्य के कृषि विभागों, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किया जाता है।

राज्य के विस्तार कार्मिकों एवं किसानों में एकीकृत कीट प्रबंध को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों और राज्य विस्तार कार्मिकों के लिए एक व्यापक शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। मौजूदा 26 एकीकृत कीट प्रबंध केन्द्रों को सुदृढ़ किया गया है और 4 नए केन्द्र खोले जा रहे हैं। कृषकों के प्रशिक्षण के लिए 1994-95 के दौरान 844 फार्मर्स फील्ड स्कूल खोले गए एवं 1995-96 में 2,200 फार्मर्स फील्ड स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है।

तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं चल रही हैं। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तिलहन कार्यक्रम से संबंधित है एवं राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम दलहन कार्यक्रमों के लिए है। नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों द्वारा फ्रंटलाइन प्रदर्शनों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है। राज्यों के कृषि विभाग के ब्लॉक प्रदर्शनों तथा मिनिकिटों के वितरण के माध्यम से प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाते हैं।

गहन कपास विकास तथा विशेष पटसन विकास कार्यक्रमों के तहत, उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।